भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3365
21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: मोटे अनाज की खेती

3365. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री ए. राजा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पोषक मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए आरएंडडी सपोर्ट दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मिलेट्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा था/दिया जा रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनाज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : मिलेट्स (श्री अन्न) को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 14 राज्यों के 212 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत पोषक-अनाज (मिलेट्स) पर वर्ष 2018-19 से एक उप-मिशन क्रियान्वित कर रहा है। एनएफएसएम-पोषक अनाज के तहत, किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकर के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक-तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों/औजारों/संसाधन-संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का क्षमता वर्धन, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनीकिट्स का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, आदि पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पोषक अनाजों के लिए उत्कृष्ठता केंन्द्रों (सीओई) और बीज केंद्रों की स्थापना जैसे प्रयासों को भी एनएफएसएम के तहत सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के दौरान कार्यान्वयन हेतु मिलेट्स (श्री अन्न) आधारित उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलएसएमबीपी) को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) स्कीम वर्तमान में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। सरकार मिलेट्स (श्री अन्न) में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए किसानों/एफपीओ/उद्यमियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से कृषि अवसंरचना कोष योजना को भी लोकप्रिय बना रही है। किसानों को मिलेट्स (श्री अन्न) की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (आईवाईएम) के रूप में मनाए जाने की दृष्टि से, भारत सरकार उत्पादन और उत्पादकता, खपत, निर्यात, मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभों के लिए जागरूकता पैदा करने, आदि की दृष्टि से कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक बहु हितधारक दृष्टिकोण क्रियान्वित कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आईवाईएम के लिए पहला वैश्विक कार्यक्रम 18 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरवमयी उपस्थिति रही। जिसमें आईवाईएम उत्कीर्ण टिकट और मुद्रा सिक्का भी लॉन्च किया गया। इस आयोजन के हिस्से के रूप में, प्रमुख मिलेट्स उत्पादक/निर्यातक देशों के छह कृषि मंत्रियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैज्ञानिकों, पद्म पुरस्कार प्राप्त लोग, किसानों, एफपीओ, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों आदि सहित 100 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों की भागीदारी के साथ एपीडा के सहयोग से एक वैश्विक स्तर की प्रदर्शनी-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित की गई थी। कई अन्य हितधारक जैसे किसान उत्पादक कंपनियों/किसानों, स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कृषि-विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), ग्राम पंचायत, सहकारी संस्थान, होटल प्रबंधन स्कूल, युवा केंद्र, आंगनवाड़ी, भारतीय दूतावास, रेल मंत्रालय और प्रवासियों आदि ने भी इस आयोजन में ऑनलाइन भाग लिया।

(ख): सरकार मिलेट्स (श्री अन्न) को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान कर रही है। आईसीएआर- इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर), हैदराबाद शेल्फ-लाइफ, खाद्य मानकों, डेटाबेस विकास, आदि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा है जिसे एनएफएसएम के तहत वित्त पोषित किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई) मिलेट्स प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और उत्पाद विकास में बाधाओं से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित कर रहा है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) स्कीम के तहत सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूरु ने असंगठित क्षेत्र में मिलेट्स आधारित उद्योगों सहित मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) कार्यक्रम के तहत, मिलेट्स प्रसंस्करण के लिए उत्कृष्टता केंद्र और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें मिलेट्स को समर्पित लगभग 8 प्रोसेसिंग लाइन्स शामिल हैं। ये लाइन्स बढ़ी हुई शेल्फ-लाइफ के साथ गुणवत्तायुक्त प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों को प्राप्त करने में सहायता करेंगी। आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान मिलेट्स पर विभिन्न चीजों जैसे प्रसंस्कृत और पके हुए मिलेट्स के पोषण मूल्यों, पके हुए मिलेट्स आहार की प्रभावकारिता, रागी आधारित आहार पूरकता के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

(ग): तीन मिलेट्स (श्री अन्न) नामत ज्वार, बाजरा और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रुपये प्रति क्विंटल

क्र.सं.	**फ़सल**	**21-2020**	**22-2021**	**23-2022**
1	ज्वार (हाइब्रिड)	2620	2738	2970
	ज्वार (मालदंडी)	2640	2758	2990
2	बाजरा	2150	2250	2350
3	रागी	3295	3377	3578

******